

## Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 12 नवंबर, 2021

### एंटी-ओपन बर्नगि कैंपेन

दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशषिट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 11 नवंबर से 11 दिसंबर, 2021 तक दिल्ली में 'एंटी-ओपन बर्नगि कैंपेन' शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'खतरनाक' स्तर पर पहुँचने के बाद की गई। ज्ञात हो कि बीते दिनों दीपावली के अवसर पर राजधानी में 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' 503 के गंभीर स्तर पर पहुँच गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू करने का नरिणय लया गया। इस अभियान के हसिसे के रूप में दिल्ली सरकार के वभिनिन वभिगों द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी, जहाँ खुले में अपशषिट जलाने संबंधी घटनाएँ होती हैं और साथ ही इन घटनाओं को रोकने का भी प्रयास कया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी वभिगों को एक वशिषिट 'एंटी डसूट सेल' बनाने का भी नरिदेश दया है। साथ ही सरकार द्वारा 'गरीन दिल्ली एप' भी शुरू कया जाएगा, जो क आम लोगों को खुले में अपशषिट जलाने की कसिी भी घटना की रपौरट करने की सुवधा प्रदान करेगा, ताक संबंधति टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।

### ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स

'हारम रडिक्शन कंसोर्टियम' द्वारा हाल ही में जारी पहले 'ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स' में नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटिन और ऑस्ट्रेलया को मानवीय और स्वास्थय-संचालति दवा नीतियों पर पाँच प्रमुख देशों के रूप में स्थान दया गया है। इस सूचकांक में पाँच सबसे कम रैकिग वाले देश ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशया, केन्या और मैक्सिको हैं। भारत 30 देशों की सूची में 18वें स्थान पर है। यह सूचकांक ड्रग नीतियों और उनके कारयान्वयन का डेटा-संचालति वैश्वकि वशि्लेषण प्रदान करता है। यह दवा नीति के पाँच व्यापक आयामों में संचालति 75 संकेतकों से बना है, इन पाँच आयामों में शामिल हैं- आपराधकि न्याय, अत्यधिक प्रतकिरयाएँ, स्वास्थय एवं नुकसान में कमी, अंतरराष्टरीय स्तर पर नरितरति दवाओं तक पहुँच एवं वकिस। यह 'हारम रडिक्शन कंसोर्टियम' संगठन की एक परयोजना है, जसिमें सहयोगी के तौर पर कई अंतरराष्टरीय गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष पर रहने के बावजूद नॉर्वे केवल 74/100 स्कोर ही प्राप्त कर सका और सभी 30 देशों एवं आयामों में औसत स्कोर केवल 48/100 रहा, जो क स्पष्ट तौर पर अंतरराष्टरीय ड्रग नीतिकी वकिलता को दर्शाता है।

### जलवायु परिवर्तन हेतु अमेरिका-चीन समझौता

कार्बन डाइऑक्साइड के दुनिया के दो सबसे बड़े उत्सर्जक चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहयोग बढ़ाने के लयि एक समझौता कया है, जसिमें मीथेन उत्सर्जन को कम करना, जंगलों की रक्षा करना और कोयले का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। ग्लासगो में आयोजति 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' (COP26) के दौरान इस समझौते की घोषणा की गई। दो सबसे बड़े कार्बन-प्रदूषणकर्त्ताओं ने कहा कि यह समझौता वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के दशानरिदेशों का उपयोग करते हुए '2020 के दशक में उन्नत जलवायु कार्रवाई' पर जोर देगा, जसिमें वर्ष 2025 में एक नया मज़बूत उत्सर्जन कटौती लक्ष्य भी शामिल है। यह समझौता डीकार्बोनाइज़ेशन में 'टोस और व्यावहारकि' नयिमों के नरिमाण का भी आह्वान करता है, साथ ही इसमें मीथेन उत्सर्जन को कम करना और वनों की कटाई का मुकाबला करना भी शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 का समझौता सभी देशों को व्यापक उत्सर्जन कटौती के माध्यम से वैश्वकि तापमान वृद्धिको 1.5°C और 2°C के बीच सीमति करने की दशाने में काम करने हेतु प्रतबिद्ध करता है।